



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 1989/ आषाढ 13, 1911

No. 409] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 1989/ SRAVANA 13, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्घोग भवानीय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1989

श्रीमित्रजनार्थ

सा. का. नि. 739 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी (संगोष्ठी) प्रवित्तियम्, 1988 (1988 वा 31) की धारा 1 की उपधारा (2) वाले प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 4 अगस्त, 1989 को एकल्हारा ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसकी धारा 4(ग) (के) जहां तक मह कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों की अहेतुआर्थी तथा अनुमत के नियामन से नन्दन्यता है। उपर्युक्त प्रवृत्त होती है।

[पा.स. 1/19/87-रा.एन.-5]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th August, 1989

G.S.R. 739(F).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 1988 (31 of 1988), the Central Government hereby appoints the 4th day of August, 1989, as the date on which the provisions of

2186GI/89

(1)

section 4(c) (in so far as it relates to prescription of qualifications and experience of the members of the Company Law Board) shall come into force.

[File No. 1/19/87-CL.V]

सा. का. नि. 740(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी प्रवित्तियम् (1956 का 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खंड (के) साथ प्रति धारा 10 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रथम:—

1. मंजिला नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का मंजिला नाम कम्पनी विधि बोर्ड के मद्दत्य (अहेतुआर्थी और अनुमत) नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदृश होते।

2. परिमाण।—इन नियमों में, जब तक कि संबंध से अन्धवा भ्रोड़त न हो:—

(क) “भ्राधारा” से कंपनी विधि बोर्ड का अध्यक्ष अभियोग है;

(ख) “कंपनी विधि बोर्ड से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित कंपनी विधि प्रकाशन बोर्ड अभियोग है;

(ग) “कंपनी विधि सेवा” से केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा नियम, 1965 के नियम 3 के अधीन गठित केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा अभियोग है;

(प) "सदस्य" से कंपनी विधि बोर्ड का सदस्य प्रभित्रेत है जिसके अत्यंत अधिकार भी है।

3. सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहमताएँ और आयुसीमा—(1) कोई व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त के लिए तब तक असूल नहीं होता जब तक कि वह—

(i) कंपनी विधि संथा का सदस्य न हो या सदस्य न रह चुका हो और उस सेवा में अतिकाल श्रेणी या उच्चत श्रेणी में पद भारण किए हुए हैं या धारण किए हुए या और जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव की श्रेणी में पिछले पद पर नियुक्त विए जाएं के लिए पात्र हो; या

(ii) केंद्रीय कमेटीयारयन्स न्यूयोर्क के अधीन भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर नियुक्त किए जाएं के लिए पात्र न हो जिसमें वेतनभान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनभान से कम न हो और वापिस उद्दीप, अर्थशाल्क, कथाप्रति या विधि में संविधित समस्याओं के निपटान के संबंध में पात्र हो और अनुभव रखता हो; या

(iii) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण न कर चुका हो; या

(iv) किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता न रह चुका हो या कुल 10 वर्ष की अवधि में कोई न्यायिक पद को धारित न कर चुका हो और भागतः अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसायी न रह चुका हो; या

(v) वर्ष से कम 15 वर्ष तक—

(क) नार्टिं अकाउन्टेट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन बार्टर्ड अकाउन्टेट के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(ख) लागत और संबंध अकाउन्टेट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन लागत लेखांकार के रूप में व्यवसायी न हो या न रह चुका हो; या

(vi) कम से कम 15 वर्ष कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की पारा 2 के खंड (45क) में यथापरिभाषित पूर्ण कानूनिक व्यवसाय करने वाले सचिव के रूप में शार्ट कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के सदस्य के रूप में कार्य करने का अनुभव न रखता हो।

(2) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने पैतालीरा वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो।

4. कंपनी विधि बोर्ड की संरचना—(1) यथागत्र नियाटम रूप से सदस्यों में से आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जो नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (i) में यथाविनियिष्ट अहतीण् रखते हो:

परन्तु, उस गिरिजा की बाबत जो कंपनी विधि संथा के निम्नी सदस्य द्वारा भरी जानी है, जहां ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है या उपयुक्त नहीं पाया जाता है, वहां, रिक्त अन्य स्रोतों से उच्चत द्वारा भरी जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष नियक्त कर सकता।

(3) उपनियम (2) में अहतीण नियुक्त किए जाने वाला अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत सरकार के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र है या जो कम से कम दीन वर्ष तक राज्य का मर्यादित रखता है।

5. भर्ती की पद्धति : (1) एक चयन बोर्ड होगा जो नियन्त्रित रूप से विद्यक द्वारा।

(i) मन्त्रिव, भारत सरकार, उच्ची न्यायालय कम्पनी कार्य विभाग

(ii) मन्त्रिव, भारत सरकार, विधि और न्याय न्यायालय, विधि कार्य विभाग,

(iii) कंपनी कार्य विभाग के भारतीय भारत नामनिर्दिष्ट भारत सरकार का कोई मन्त्रिव, और

(iv) अत्रिध, यदि पद पर हो, और उसकी पुनःनियुक्ति पर विवार नहीं किया जा रहा है।

(2) सचिव, भारत सरकार, उच्ची न्यायालय, कंपनी कार्य विभाग, यथन बोर्ड का अधिकार होगा।

(3) चयन बोर्ड, सदस्यों के रूप में नियुक्ति में विविधियाँ की नियापन द्वारा उसके लिए आवैदत आमंत्रित करने के पश्चात् उन व्यक्तियों में से करेगा, जो कंपनी कार्य विभाग द्वारा तैयार नहीं गई पात्र अध्यक्षियों की सूची में हैं।

(4) एन्ड्रीय सरकार, चयन बोर्ड की विकारिशी पर विचार करने के पश्नात् इन यातार नियापन की गई नाम सूची में से व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी। किंतु यही केंद्रीय सरकार नामसूची में से किसी या सभी नामों को अस्वीकृत कर सकती।

(5) इन नियम की कोई बात कंपनी विधि बोर्ड के किसी ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति को लागू नहीं होगी जो इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा है, यदि वह इन नियमों के अनुसार ऐसी नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र है।

6. नियन्त्रित का दृष्ट्या योग्यता:—किसी व्यक्ति को सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित किसी नियन्त्रित बोर्ड द्वारा न्यायिक व्यक्ति न कर दिया हो, यदि उसे किसी समतुल्य प्राधिकारी द्वारा पहले ही योग्य घोषित न कर दिया गया है।

7. सदस्य द्वारा यथागत्र:—फोर्ड सदस्य, किसी भी समय नियन्त्रित में अस्ते हस्तांतर से केंद्रीय सरकार को भंगोत्तित करते हुए अपने पद में राज्यपत्र दे सकेगा :

परन्तु यह कि, सदस्य जब तक कि उसे केंद्रीय सरकार द्वारा पहले ही पद यथागत्र के लिए अनुशासित न किया गया हो या ऐसी सूचना प्राप्ति से तीन मास की अवधि मापात्त न होने तक या ऐसे किसी व्यक्ति के उसके उत्तरवर्ती के रूप में सन्धृक रूप से नियुक्त हुआ है अपने पद पर न आने तक या अपने पद की अधिक समाप्त न होने तक, जो भी पूर्वीर ही पद धारण करता रहेगा।

8. कुल परिस्थितियों में सदस्य का पद से छाटा जाना:—केंद्रीय सरकार किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी। जो,

(क) न्यायनिर्णीत दिवालिया है, या

(ख) दिनी ऐसे अवरात के लिए सिद्धांश द्वारा जा चुका है जिसमें केंद्रीय सरकार की राज्य में नैतिक अधिकार अस्तवैति है, या

(ग) दिनी राज्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अद्यता हो गया है,

(घ) दिनी व्यक्ति बोर्ड अधिकार द्वारा जा चुका है जिसके उसके सदस्य के रूप में किसी पर ग्राहित कूल प्रसाद पहुँच भी संभवता है, या

(८) अपने पद का इतना दुरुपयोग कर नुक्का है कि उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिष्ठित प्रकाव पड़ता हो।

९. सदस्यों के पदों में आकर्षिक विविध न्यायः—नियम ७ और नियम ८ के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य के ल्यापक या पद से हटाए जाने से हुई आकर्षिक विविध को भी नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

१०. सदस्यों के पद की अवधि:—कोई सदस्य अपना पद छोड़ करने की तरीख से एक समय में पांच वर्ष की अवधि के लिए या अधिक के लिए कि कहुः—

(क) आवाहन वर्ष की आय प्राप्त नहीं कर लेता; और

(ब) वह अध्यक्ष है तो साठ वर्ष की आय प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पूर्वीर ही, पद धारण करता रहेगा।

११. वेतन और अवृत्ति:—(१) अध्यक्ष वो ७३००-१००-७६०० के वेतनमात्र में वैतन का मंदाय दिया जाएगा।

(२) सदस्य को ६९००-२००-६७०० रु. के वेतनमात्र में वैतन का संतुल्य दिया जाएगा।

(३) अध्यक्ष और सदस्य वे भत्ते लेने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के प्रशस्ति श्रेणी के अधिकारियों को आद्य है।

१२. निर्विचलन:—यदि इन नियमों के निर्विचलन के मंडेंड में कोई प्रश्न उठता है तो उसे मेन्ट्रिय सरकार को उसके विविधत्व के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

१३. आवृत्ति:—इन नियमों की कोई जो वात सेन्ट्रीय सरकार द्वारा इस नियमित जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भाषापूर्व सेनिकों और व्यक्तियों के अन्य विवेक प्रकारों के लिए किए गए आवधान आय सीमा में भी जाने वाली दृष्ट और उन्हें दी जाने वाली अन्य विविधत्वों पर प्रकाव नहीं खालीगी।

१४. पद और गोपनीयता की जगह:—अध्यक्ष या सदस्य के रूप में विवक्त प्रत्येक अधिकारी अपना पद जानकारी से पूर्ण इन नियमों से उत्तराधि नियम I और नियम II में पद जीर्ण गोपनीयता की शपथ लेगा और उन पर हाराधर करेगा।

१५. सेवा की अन्य जातेः—किसी भवस्य की सेवा की ये जातें जिनकी वातावरण इन नियमों में कोई दबावन्य नहीं किया गया है वैसी हींपी जैसी कि उस समय सेन्ट्रीय सरकार के सलामान नियमित के अन्य कर्मचारियों की जागू हैं।

प्रत्यक्ष :

(नियम १४ विविध)

कमानी विविध बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद का प्रस्तुप

“मैं आमुक, जो कमानी विविध बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुआ हूँ, इसके द्वारा दी गयी शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं प्रदाता/सदस्य के रूप में आपने कर्तव्यों का आकर्षक और पूर्ण अनुसारण के निर्वहन करवाना चाहा तथा मैं अपने पदपात्र अनुसार आय देणा के बिना निर्वहन कराऊ।

प्रस्तुप -II

(नियम १४ विविध)

कमानी विविध बोर्ड अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद और गोपनीयता का प्रस्तुप

‘मैं, आमुक जो कमानी विविध बोर्ड का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त हुया हूँ, इसके द्वारा दी गयी शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय

कमानी विविध बोर्ड के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अवश्य कुछ ज्ञात हीगा किसी व्यक्ति या व्यवितरणों को, तब के विवाय जब कि ऐसे अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रतिष्ठित हो, मैं प्रथम या अप्रथम रूप में संसूचित वा प्रकट नहीं करूँगा।”

[फा. से १/१९/८७-सी.ए. ८८
सी. आर. तुरंदराजन, संयुक्त मंचिक

G.S.R. 740(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 10E read with clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely,—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Company Law Board members (Qualifications and Experience) Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Chairman” means Chairman of the Company Law Board;

(b) “Company Law Board” means the Board of Company Law Administration constituted under sub-section (1) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(c) “Company Law Service” means the Central Company Law Service constituted under rule 3 of the Central Company Law Service Rules, 1965;

(d) “Member” means a member of the Company Law Board and includes the Chairman.

3. Qualifications and age limit for appointment of Members.—(1) A person shall not be qualified for appointment as a member unless he —

(i) is, or has been, a member of the Company Law Service and is holding, or has held, a post in super-time grade or selection grade in that service and is eligible to be appointed to a post in the grade of Joint Secretary to the Government of India; or

(ii) is, eligible to be appointed as a Joint Secretary to the Government of India under the Central Staffing Scheme, or to any other post under the Central Government carrying a scale of pay which is not less than that of Joint Secretary to the Government of India, and has adequate knowledge of, and experience in dealing with the problems relating to commerce, industry, economics, taxation or law; or

(iii) has, for at least 10 years, held a judicial office in the territory of India; or

(iv) has for at least ten years, been an advocate of a High Court; or has partly held a judicial office and has been partly in practice as an advocate for a total period of ten years; or

- (v) is, or has been, for at least fifteen years in practice, as a—
 - (a) Chartered Accountant under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949); or
 - (b) Cost Accountant under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959);
- (vi) has, for at least fifteen years, working experience as a Secretary in whole time practice as defined in clause (45A) of section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and is a member of the Institute of Company Secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980).

(2) A person shall not be eligible for appointment as member unless he has completed the age of forty-five years.

4. Composition of the Company Law Board.—(1) As nearly as may be, one-half of the Members shall by person possessing qualifications as specified in clause (i) of sub-rule (1) of rule (3) :

Provided that in respect of a vacancy which is to be filled by a member of the Company Law service, where either no such person is eligible or found suitable for appointment, the vacancy shall be filled in by selection from other sources

(2) The Central Government shall appoint one of the members to be the Chairman.

(3) The Chairman, to be appointed under sub-rule (2), shall be a person who is eligible to be appointed as an Additional Secretary to the Government of India; or who has at least for three years held office of the member.

5. Method of recruitment.—(1) There shall be a Selection Board consisting of—

- (i) The Secretary to the Government of India, Ministry of Industry, Department of Company Affairs;
- (ii) The Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs;
- (iii) Any Secretary to the Government of India, nominated by the Minister incharge of the Department of Company Affairs; and
- (iv) The Chairman, if in Office and he is not being considered for re-appointment.

(2) The Secretary to the Government of India, Ministry of Industry, Department of Company Affairs shall be the Chairman of the Selection Board.

(3) The Selection Board shall recommend persons for appointment as members from amongst the persons on the list of eligible candidates prepared by the Department of Company Affairs after inviting applications therefor by advertisement.

(4) The Central Government shall, after taking into consideration the recommendations of the Selection Board, appoint persons out of the panel so recommended. However, it shall be open to the Central Government to reject any or all the names on the panel.

(5) Nothing in this rule shall apply to the appointment of any member of the Company Law Board functioning as such immediately before commencement of these rules, in case he is otherwise eligible for such appointment as per these rules.

6. Medical Fitness.—No person shall be appointed as member unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose, unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

7. Resignation by a member.—A member may, by writing under his hand addressed to the Central Government, resign his office at any time:

Provided that the member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish office sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of receipt of such notice or until a person duly appointed as a successor enters upon his office or until the expiry of his term of office whichever is earliest.

8. Removal of members from office in certain circumstances.—The Central Government may remove from office any member, who—

- (a) has been adjudged an insolvent; or
- (b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or
- (c) has become physically or mentally incapable of acting as such member; or
- (d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member; or
- (e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

9. Casual vacancy in the office of members.—A casual vacancy caused by the resignation or removal of the Chairman or any other member of the Board under rules 7 and 8 shall be filled by fresh appointment.

10. Term of office of members.—Every member shall hold office for a term of five years at a time from the date of his assumption of office or until he attains,—

- (a) the age of fifty-eight years; and
- (b) if he is the Chairman, the age of sixty years, whichever is earlier.

11. Salary and allowances.—(1) The Chairman shall be paid salary in the scale of Rs. 7300-10/-7600.

(2) A member shall be paid a salary in the scale of Rs. 5900-200-6700.

(3) The Chairman and members shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Central Government Officer of the first grade.

12. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be referred to the Central Government for its decision.

13. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Schedule Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Oaths of office and secrecy.—Every person appointed to be Chairman or a member shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and of secrecy in Forms I and II annexed to these rules.

15. Other Conditions of Service.—The conditions of service of a member in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as may for the time being be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

FORM I

(See Rule 14)

Form of oath of Office for Chairman|member of the Company Law Board.

"I, A.B., having been appointed as Chairman|member of the Company Law Board do solemnly affirm|do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chairman|member to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will."

FORM II

(See rule 14)

Form of oath of secrecy for Chairman|member of the Company Law Board.

"I, A.B., having been appointed as Chairman|member of the Company Law Board, do solemnly affirm|do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chairman|member of the said Company Law Board except as may be required for the due discharge of my duties as Chairman|Member."

[File No. 1/19/87 C.L. V.]
C. R. SUNDARARAJAN, Jt. Secy.

